जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

चूरू

Rashtradoot

फोनः- 256906, 256907, फैक्सः- 01562-256908 वर्षः 14 संख्याः 165 प्रभात चूरू, बुधवार 12 अक्टूबर, 2022 पो. रजि. न. चूरू/084/2019-21 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

एक नए शोध के अनुसार भेड़िए भी इंसान के दोस्त हो सकते हैं। या फिर यूँ कह सकते हैं कि एक समय भेड़िए इंसान के बैस्ट फ्रैंड थे, बाद में हमने उन्हें कुत्तों में बदल दिया। स्वीडन के वैज्ञानिकों ने साबित किया है कि भेड़िए अजनबी और परिचित व्यक्तियों में अंतर कर सकते हैं और परिचितों के प्रति ज्यादा स्नेह प्रदर्शित करते हैं। यही नहीं, भेड़िए अगर तनाव ग्रस्त हों तो परिचित व्यक्ति उन्हें शांत कर सकते हैं। वैज्ञानिकों ने 10 भेड़ियों व 12 कुत्तों पर प्रयोग किया, यह देखने के लिए कि तनाव में वे कैसा व्यवहार करते हैं। भेड़ियों ने उस व्यक्ति की तरफ ज्यादा प्रेम दर्शाया जिसे वे जानते थे। वो उस व्यक्ति के पास गए और काफी देर तक उसके प्रति अपना प्रेम जताते रहे। स्वीडन की स्टॉकहोम युनिवर्सिटी के डॉ. हैनसन वीट, जो शोध के मुख्य लेखक हैं, ने कहा, एकदम साफ है कि भेड़िए भी कुत्तों की तरह अजनबी व्यक्ति के मुकाबले परिचित को ज्यादा तवज्जो देते हैं, लेकिन जो बात ज्यादा रोचक थी, वो यह कि टैस्ट की स्थिति से कुत्तों पर खास प्रभाव नहीं पड़ा जबकि भेड़िए इससे प्रभावित हुए और वे टैस्ट रुम में यहां वहां घूमते नज़र आए। उल्लेखनीय बात यह थी कि, जब उस व्यक्ति ने कक्ष में प्रवेश किया जिसने जीवन भर भेड़ियों की देखरेख की थी, तो भेड़िए शांत हो गए। इसका अर्थ यह है कि जाने -पहचाने व्यक्ति भेड़ियों का सामाजिक तनाव शांत करते हैं। ये नतीजे इस सोच का खंडन करते है कि कुत्तों का इंसानों से लगाव तब ही बढ़ा जब इंसान ने उसे पालतू बनाया। इकॉलाजी एंड इवोल्यूशन जर्नल में छपा यह शोध दर्शाता है कि इंसानों से लगाव का रिश्ता सिर्फ कुत्तों में ही नहीं पनपा है। डॉ. वीट ने कहा, "इससे यह भी साबित होता है कि जानवरों का उन व्यक्तियों से मजबूत संबंध होता है जो उनके परिचित होते हैं। शोध टीम ने कुत्तों और भेड़ियों के बच्चों को तब से पाला जब वे 10 दिन के थे फिर जब वे 23 हफ्ते के हुए तब यह प्रयोग किया गया।"

गहलोत की विदाई क्यों अटकी हुई है?

हाई कमान चाहता है, नया अध्यक्ष इस निर्णय का क्रियान्वयन कराये

- प्रियंका गांधी ने अध्यक्ष पद के चुनाव की प्रक्रिया के बीच यू.पी. का प्रदेशाध्यक्ष बदला था, इस पर प्रतिक्रिया ठीक नहीं हुई। वरिष्ठ नेताओं का मत था कि, यह निर्णय नये अध्यक्ष पर छोड़ना ज्यादा उचित रहता।
- इसीलिये अब 17 अक्टूबर के बाद नये अध्यक्ष के चुनाव तक, गहलोत का "फेयरवैल" स्थगित हो गया है।
- जैसा कि लग रहा है, खड़गे का अध्यक्ष बनना लगभग तय है तथा खड़गे भी पर्यवेक्षक के रूप में जयपुर आये थे तथा उस समय जो ड्रामा हुआ था, उससे क्षुब्ध होकर खड़गे ने तीखी टिप्पणी की थी कि, गत चालीस साल में उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष की इतनी बेइज़्ज़ती पहले कभी नहीं देखी।
- गहलोत ने भी अपनी खिलाफत को मजबूती देते हुए अडानी का काफी सम्मान किया, इन्वैस्ट समिट में तथा अमित शाह के बेटे का नाम लेकर राजस्थान में पूंजी निवेश के लिये आमंत्रण देना, हाई कमान को सीधा मैसेज देना था कि, अब उनको अमित शाह का प्रोटेक्शन प्राप्त है, अतः अगर उन्हें हटाकर पायलट को मु.मंत्री बनाया गया तो, सरकार गिरा देंगे भाजपा की मदद लेकर।

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 11 अक्टूबर। यह सोनिया गांधी की ओर से एक और तिरस्कार है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अनदेखी कर पार्टी के शीर्ष नतृत्व ने उन्हें पार्टी के प्रतिनिधि के रुप में मुलायम सिंह यादव के अंतिम संस्कार में भाग लेने के लिए सैफ़ई नहीं भेजा। कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व करने के लिए वहां जो दो व्यक्ति भेजे गए हैं, वे हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ। यदि विद्रोह से पहले जैसी सामान्य स्थिति होती तो पार्टी के देश में दो मुख्यमंत्रियों में से एक अशोक गहलोत को उनके अंतिम संस्कार में भाग लेने के लिए भेजा जाता।

लेकिन अशोक गहलोत पीछे नहीं रहना चाहते। "मैं परवाह नहीं करता" वाला रवैया दर्शाते हुए गहलोत भी सैफ़ई के लिए रवाना हो गए, अपने विधायकों को यह संदेश देने के लिए कि वे अब भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जमे हुए हैं और उन्हें सोनिया गांधी का विश्वास प्राप्त है।

वास्तव में गहलोत का विद्रोह एक ऐसी स्थिति में पहुंच चुका है कि यहां तक गांधी परिवार का संबंध है, वह अपनी ढपली अलग ही बजा रहे हैं। गौतम अडानी की मेजबानी करने का उनका निर्णय कांग्रेस नेतृत्व को यह बताने का एक सुनियोजित कदम था कि वह उन्हें हटाने की किसी भी स्तर पर कोशिश करके देख ले। यहां तक कि उन्होंने अमित शाह के पुत्र जय. शाह को भी राजस्थान में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

मुलायम के जाने के बाद सपा का विभाजन रूक सकेगा?

शिवपाल, आजम खान व मायावती मिलकर मुलायम सिंह की विरासत पर कब्जा कर लेंगे?

- मुलायम सिंह ने अपने जीवन काल में अपने पुत्र अखिलेश को उत्तराधिकारी घोषित तो कर दिया था। पर अब ऐसा प्रचार हो रहा है कि, अखिलेश के कामकाज से स्वयं मुलायम भी थोड़ा खिन्न थे, अपने अंतिम दिनों में। शिवपाल व उनका समूह, जिसमें आज़म खान व अमर सिंह भी थे, एक समय प्रचारित करने लगे थे कि, जिस जल्दबाजी से मुलायम सिंह को सपा के अध्यक्ष पद से हटाया गया व मुलायम सिंह के पुराने साथियों को घर भेजा गया, उससे अखिलेश औरंगज़ेब हो गये हैं।
- बहरहाल, अखिलेश के समक्ष इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती होगी मैनपुरी संसदीय सीट पर सपा का कब्जा बरकरार रख सकें।
- इसके अलावा सपा के पुराने गढ़ आज़मगढ़, कन्नौज, संभल, रामपुर आदि संसदीय सीटों पर सपा हार चुकी है, पर एक बार फिर सपा का परचम लहराये।

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 11 अक्टूबर। मुलायम सिंह यादव के युग के अवसान के साथ ही, समाजवादी पार्टी एक बार फिर विरासत के युद्ध की तरफ बढ़ती प्रतीत हो रही है। ऐसी अपेक्षा की जा रही है कि समाजवादी पार्टी के इस स्वर्गीय संस्थापक एवं दिग्गज नेता के भाई शिवपाल यादव पार्टी को तोड़ने का पूरा-पूरा प्रयास कर सकते हैं। उनकी तमाम स्वास्थ्य संबंधी तकलीफों तथा पिछली तीन साल में सक्रिय राजनीति को अलविदा कह देने के बावजूद, मुलायम की मौजूदगी मात्र से ही यह तो सुनिश्चित था ही कि पार्टी के प्रथम परिवार के प्रतिद्वंदी गुटों के बीच एक हद तक सामान्य शिष्टाचार बना रहेगा। जहाँ उत्तराधिकार का मुद्दा मुलायम के जीवन-काल में ही अखिलेश यादव के पक्ष तय हो गया था, वहीं जो स्थिति उभर कर सामने आई थी, उसमें सपा-संस्थापक स्वयं को सहज महसूस नहीं कर रहे थे। वस्तुतः, अखिलेश ने अपने पिता को सपा के अध्यक्ष पद से हट जाने के लिये बाध्य कर दिया था तथा बहुत से पुराने दिग्गजों, जिनमें आज़म खान, शिवपाल तथा स्व. अमर सिंह भी शामिल थे, को दरकिनार कर दिया था। अखिलेश के कार्यों ने उन्हें औरंगज़ेब का प्रतिरूप बना दिया था, जिसने सम्राट बनने के लिये अपने पिता को कैद कर दिया था। ऐसी संभावना दिखाई दे रही है कि शिवपाल गुट आगामी सप्ताहों तथा महीनों में इस पूरे घटनाक्रम का लाभ लेना चाहेगा। ऐसी चर्चा है कि शिवपाल, आज़म तथा मायावती की तिकड़ी अखिलेश के नेतृत्व वाले अधिकृत सपा गुट को चुनौती देने के लिए एकजुट होने की कोशिश में हैं।

ऐसे समय पर, जब नरेन्द्र मोदी द्वारा संचालित भाजपा, सपा के पुराने गढ़ों में उसे खत्म करने में जुटी हुई है, अखिलेश के सामने पहली और बहुत बड़ी चुनौती यह होगी कि वे मैनपुरी लोकसभा को बरकरार रखें, जो उनके पिता के पास रही थी। मुलायम 10 बार विधायक तथा 7 बार सांसद रहे थे। इस सात अवसरों में वे पाँच बार मैनपुरी लोकसभा सीट से ही जीते थे। जिस बार वे चुनाव नहीं लड़े थे, सपा प्रत्याशी इस सीट से जीता था। यही स्थिति उन अन्य चुनाव क्षेत्रों में भी रही, जो सपा का गढ़

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

पंकज मित्तल राजस्थान के नए सी.जे.

- केन्द्र सरकार ने पंकज मित्तल को राजस्थान हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया, इसी के साथ जम्मू-कश्मीर के लिए जस्टिस ए.एम. माग्रे और कर्नाटक के लिए जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले को चीफ जस्टिस के पद पर नियुक्ति दी।

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 11 अक्टूबर। केन्द्र सरकार ने मंगलवार को राजस्थान हाई कोर्ट, जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख हाई कोर्ट तथा कर्नाटक के नए चीफ जस्टिस नामित किए। जस्टिस पंकज मिथल राजस्थान हाई कोर्ट, जस्टिस ए.एम. माग्रे जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख हाई कोर्ट और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले कर्नाटक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनाए गए हैं।

जस्टिस मिथल को शुरु में 4 जनवरी 2021 को जम्मू एवं कश्मीर

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

प्रदेश प्रभारी अरूण सिंह ने नेताओं की घर वापसी पर दिया बड़ा बयान

अरूण सिंह ने कहा भाजपा प्रदेशाध्यक्ष पूनिया से बात करके ही कमेटी करेगी घर वापसी का फैसला

- 21 अक्टूबर को राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा कोटा में लेंगे, कोर कमेटी की बैठक, उसमें नेताओं की घर वापसी पर फैसला होगा।
- ये नेता हैं, सुरेन्द्र गोयल, देवी सिंह भाटी, मानवेन्द्र सिंह, सुभाष महरिया और राजकुमार रिणवा।
- रोचक बात यह है कि, पार्टी का एक धड़ा इनकी घर वापसी का विरोध कर रहा है।

जयपुर, 11 अक्टूबर (का.सं.)। भाजपा में पिछले लोकसभा व विधानसभा चुनावों के दौरान पार्टी छोड़कर जाने वाले नेताओं की घर वापसी को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री एवं प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने बड़ा बयान दिया। इस दौरान सिंह ने कहा कि भाजपा छोड़ कर जा चुके नेताओं की घर वापसी पर फैसले के लिए एक कमेटी का गठन होगा। कमेटी नेताओं के प्रोफाइल और तमाम पहलुओं पर चर्चा करके रिपोर्ट तैयार करेगी।

उन्होंने कहा कि जो नेता पार्टी की नीतियों में विश्वास करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किए जा रहे कामकाज से प्रभावित होकर पार्टी में आना चाहेगा उसे ही पार्टी में शामिल करवाया जाएगा। कमेटी अपनी रिपोर्ट प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष सतीश पूनिया को सौंप देगी और पूनिया उसके बाद अपनी सहमति देकर अपनी रिपोर्ट पार्टी आलाकमान को देंगे।

विधानसभा और लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा छोड़कर जाने वाले नेताओं की घर वापसी को लेकर इन दिनों प्रदेश भाजपा में चर्चाएं जोरों पर हैं। हालांकि जिन आधा दर्जन नेताओं की घर वापसी की बात कही जा रही है। उनका फैसला पार्टी की कोर कमेटी करेगी

पार्टी की कोर कमेटी की बैठक 21 अक्टूबर को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में कोटा में आयोजित होगी जिसमें नेताओं की घर वापसी का फैसला होगा। पार्टी छोड़ चुके सुरेंद्र गोयल, देवी सिंह भाटी, मानवेंद्र सिंह, सुभाष महरिया और राजकुमार रिणवा का फैसला पार्टी की कोर कमेटी की बैठक में होगा।

वही दिलचस्प बात तो यह है कि एक तरफ तो नेताओं की घर वापसी का फैसला पार्टी कोर कमेटी करेगी लेकिन पार्टी कोर कमेटी में ही कई नेता ऐसे हैं जो इन नेताओं की घर वापसी का विरोध कर रहे हैं। कोर कमेटी के सदस्य और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और देवी सिंह भाटी के बीच अदावत जगजाहिर है इसके अलावा केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी और मानवेंद्र सिंह के बीच भी लंबी अदावत चली आ रही है ऐसे में पार्टी का एक धड़ा ही इनकी घर वापसी का विरोध कर रहा है।

प्रदेश पदाधिकारी बैठक में भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री एवं प्रदेश प्रभारीअरुण

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

बार चुनाव का रास्ता साफ

- हाई कोर्ट ने बार काउन्सिल ऑफ इण्डिया के आदेश पर लगाई रोक।

जयपुर, 11 अक्टूबर (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने देश के अधिवक्ताओं की नियामक संस्था बार काउन्सिल ऑफ इंडिया (बी.सी.आई.) के गत तीन अक्टूबर के राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव पर रोक लगाने के आदेश पर रोक लगा दी है। ये चुनाव 18 नवम्बर को होने है। इसके साथ ही अदालत ने मामले में बी.सी.आई., बार काउन्सिल ऑफ राजस्थान और हाईकोर्ट बार एसोसिएशन और बी.सी.आई. में याचिका दर्ज करने वाले सुमेर सिंह ओला को नोटिस जारी कर पांच सप्ताह में जवाब तलब किया है।

जस्टिस महेन्द्र गोयल ने यह आदेश हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व महासचिव और अध्यक्ष पद के प्रत्याशी प्रहलाद शर्मा व रोहन जैन सहित अन्य की याचिका पर दिए तथा स्पष्ट किया कि

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

हिन्दी की खिलाफत दक्षिण भारत की राजनीति का आधार बनेगी आगामी चुनावों में?

तमिलनाडू के मुख्यमंत्री स्टालिन ने गृह मंत्रालय के आधीन भाषा के मसले पर गठित संसदीय समिति की रिपोर्ट को आधार बनाकर केन्द्रीय सरकार व भाजपा को काफी खरी-खोटी सुनायी और धमकी भी दे डाली कि, भाजपा का भी वही हश्र होगा जो कांग्रेस का 1960 के दशक में हुआ था, दक्षिण के हिन्दी विरोधी आंदोलन के कारण

- मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि, हिन्दी को उच्च शिक्षा में पढ़ने-पढ़ाने का माध्यम होना चाहिये। उच्च शिक्षा का मतलब, आई.आई.टी., आई.आई.एम., केन्द्रीय विश्वविद्यालयों व एम्स से है।
- स्टालिन के अनुसार इससे दक्षिण भारत के लोग देश में सैकण्ड क्लास नागरिक हो जायेंगे।
- केन्द्रीय सरकार का यह कदम संविधान के भी खिलाफ होगा, क्योंकि संविधान में सभी क्षेत्रीय भाषाओं से बराबर का बर्ताव करने की व्यवस्था प्रदत्त की गई है।
- "हिन्दी को अंग्रेजी की जगह बिठाने से हिन्दी भाषी लोगों को नाजायज लाभ मिलेगा।"

-लक्ष्मण वैंकट कुची-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 11 अक्टूबर। तमिलनाडू के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने केन्द्र सरकार पर भाषा के मुद्दे पर फूट डालने वाला एजेंडा अपनाने का आरोप लगाते हुए, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से आग्रह किया है कि इस कोशिश को बंद करें, जो देश की एकता को नुकसान पहुँचा सकती है।

हाँ, अगर आई.आई.टी., आई.आई.एम. एम्स तथा केन्द्रीय विश्वविद्यालयों जैसी ऊँचे पढ़ाई की भाषा के रूप में अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी को लाने की केन्द्र की कथित कोशिश के संबंध में मीडिया रिपोर्ट की बात करें तो भाषा का मुद्दा सचमुच तथा सोच-समझकर 2024 के लोकसभा चुनावों की खातिर शुरू किया गया है।

सरकार के खुले इरादों, जो गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता वाली एक संसदीय समिति की रिपोर्ट में निहित हैं, का हवाला देने वाली इस मीडिया रिपोर्ट के चंद घंटे बाद ही तमिलनाडू के मुख्यमंत्री ने सरकार की इस कथित कोशिश पर बड़ा सख्त प्रहार किया।

हाँ, तो यह भाषाई युद्ध सचमुच शुरू हो गया है तथा इसकी चिनगारियाँ आम चुनाव की तैयारियों के दौरे तक पहुँचेगी। हिन्दी को देश की साझा भाषा के रूप में "थोपने" तथा केन्द्रीय विश्वविद्यालयों एवं उच्च शिक्षण संस्थानों द्वारा हिन्दी को एक सामान्य भाषा के रूप में अपनाने के खिलाफ तमिलनाडू के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन मजबूती से खड़े हो गये हैं। उन्होंने कहा कि केन्द्र की इस चेष्टा से दक्षिण भारतीय लोग दोयम दर्जे के नागरिक बन कर रह जायेंगे।

मीडिया के एक वर्ग में प्रकाशित इस रिपोर्ट पर, चेन्नई में जारी किये गये एक कठोर बयान के अंतर्गत तमिलनाडू के मुख्यमंत्री ने केन्द्र को राज्य में हुये हिन्दी-विरोधी आंदोलन की याद दिलाई तथा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से कहा कि वे देश में एक और भाषाई युद्ध न भड़काएं।

मीडिया के विभिन्न वर्गों के जरिये सामने आई "पार्लियामैन्ट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज" की विषय वस्तु की रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, स्टालिन ने कहा कि अगर यह क्रियान्वित हुई, तो गैर हिन्दी भाषी अपार जनसमूह उसके ही देश में दोयम दर्जे के नागरिकों के रूप में आयेगा।

उन्होंने कहा, "हिन्दी को थोपा

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

नया चुनाव चिन्ह

- शिव सेना का शिंदे गुट अब तक पृथक क्षेत्रीय पार्टी बन गया है, इसे ना केवल अलग नाम मिला है, बल्कि "दो तलवार और ढाल" का चुनाव चिन्ह भी मिला है।

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 11 अक्टूबर। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गुट को मंगलवार को अन्ततः "दो तलवार और एक ढाल" का चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया और उनकी पार्टी का नाम होगा "बाला साहेबांची शिवसेना"।

ढाल-तलवार पूर्ववर्ती पीपुल्स डैमोक्रेटिक मूवमैंट के लिए आरक्षित था। उसकी वर्ष 2004 में एक राज्य पार्टी के रूप में मान्यता रद्द कर दी गई और आगे जाकर उसे 26.12.2016

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)